Shri P. C. Borooah: May I know whether Government is aware of the fact that the poor peasants are still left at the mercy of the private money-lenders and Mahajans, particularly in a State like Assam, where rural credit facilities are practically nil; if so, whether there is any proposal to set up such banks there to augment the credit facilities to the rural people?

Mr. Speaker: Here the question is about a one-man bank at one particular place and the result of that. He can raise it in general discussion some time later on.

Shri Hari Vishnu Kamath: Is the Minister aware that one of the private banks in our country has been experimenting for sometime now with branches manned wholly by women—I believe a branch has been opened in Delhi also—and if so, has the experiment been successful and does the Government propose to emulate that example?

Mr. Speaker: That does not arise.

Shri Hari Vishnu Kamath: Like a one-man branch, all women's branch.

Shri B. R. Bhagat: I am not aware of that.

Shri Hari Vishnu Kamath: You are not aware? You have got it in Delhi.

Shri Narendra Singh Mahida: May I know whether other banks have also opened such branches, and how do they compare in their working?

Shri B. R. Bhagat: As I said, including this, five banks, all subsidiaries of the State Bank have opened this experimental one man's branch in five places.

Shri Balakrishnan: Compared with the working of the other banks there is much delay in the State Bank in its daily routine transactions. So, may I ask the Government to see that the delay is not there?

Mr. Speaker: It is a suggestion.

Shri B. R. Bhagat: Delay in the State Bank is a different question.

नगरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या में विषमता

+

*1487. **श्री मधु लिमये :**
श्री यशपाल सिंह :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विभूति मिश्र :

क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भूतपूर्व इस्पात तथा खान मंत्री श्री संजीव रेड्डी के हैदराबाद में इन्टक सम्मेलन में दिये गये उस भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने नगरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या के जीवन स्तर में समानता लाने की आवश्यकता पर जोर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने तीन पंचवर्षीय योजनाओं का इस विषमता पर जो प्रभाव हुआ है उसका अध्ययन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस अध्ययन के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

जी, हां । अपने भाषण के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि "ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के मध्य विषमता स्पष्ट थी" । उन्होंने जो स्थिति बताई वह वस्तुतः ठीक है ।

इस विषमता पर तीन पंचवर्षीय योजनाओं के क्या सूक्ष्म प्रभाव पड़े, इसके बारे में कोई मात्रात्मक अनुमान नहीं लगाया गया है ।

परन्तु यह सब जानते हैं कि तीन योजनाओं में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के सम्बन्ध में जो विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं तथा कार्यान्वित की गई है उनका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को लाभान्वित करना था ।

श्री मधु लिमये : जो विवरण रखा गया है उस में मंत्री महोदय ने लिखा है कि—

> "No quantitative assessment has been made of the precise effects of the three Five Year Plans on this disparity."

इन योजनाओं के खत्म होने के पश्चात् भी इन के पास ये जरूरी आंकड़े नहीं हैं कि नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य क्या विषमतायें हैं तथा इनके क्या कारण है ? राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी दादाभाई नारोजी, रानडे तथा गोखले, जिनकी जन्म शताब्दी हम मनाने जा रहे है, इन्होंने कहा था कि 6–7 करोड़ लोग बिना खाये हर दिन सो जाते हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनको इस बात का पता है कि इस वक्त करीब-करीब 10–12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक दफ़ा खाते हैं और रात में बिना खाये सो जाते हैं देहाती तथा शहरी विषमता के कारण, इसके बारे में वे क्या ठोस योजना बनाने जा रहे है ?

श्री ल० ना० मिश्र : ये आंकड़े तो कल्पना की बात है.....

श्री मधु लिमये : कल्पना की बात नहीं है, यह दादाभाई नारोजी ने लिखा था, आपके पास तो आंकड़े नहीं है, आप मेरी बात किस आधार पर काट रहे है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं काट नहीं रहा हू, लेकिन ये आंकड़े अभी कल्पना की बात है । मेरे पास इतने साधन रहते हुए भी, हम किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुचे है । 10-12 या 15 करोड़ पर आप पहुंच सकते है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह सत्य है कि देहाती इलाको में रहने वालों की व्यवस्था ठीक नहीं है, जितना उनके लिये होना चाहिये, उतना नहीं है । आपने पूछा की क्या योजना बना रहे हैं, पंच वर्षीय योजनाओं में इनके लिये खास ध्यान रखा है ताकि देहाती क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया जाये । यदि माननीय सदस्य सुनना चाहें तो मैं कहना चाहता हू कि प्रथम योजना में 800 करोड़ रुपया देहाती क्षेत्र पर खर्च करने की व्यवस्था थी । द्वितीय में 1670 करोड़ की थी, तृतीय में 4800 करोड़ की थी । चौथी का जानना चाहें तो मैं बता सकता हूं कि लघु सिंचाई में जहां पहले 990 करोड़ था वहां अब 2372 करोड़ किये जा रहे है, विल्लेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के मामले में 75 परसेंट बढ़ाने की बात हो रही है, रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के लिए शत-प्रतिशत, मौ परसेंट बढ़ाने की बात है, एलीमैंटरी एजुकेशन में 100 प्रतिशत बढ़ाने की बात है । बैकवर्ड क्लासिस के लिए 188 करोड़ में से 169 करोड़ देहातों में खर्च होंगे । देहातों की हालत आप देखेंगे तो पता चलेगा कि अच्छी हुई है लेकिन जितनी होनी चाहिये थी, नहीं हुई है, यह भी सही है ।

श्री मधु लिमये : बिहार के सिंचाई मंत्री ने एक ब्यान दिया था कि अब की बार रबी की जो फसल होगी उस में हम मुफ्त सिंचाई का इंतजाम करेंगे । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि देहाती क्षेत्रों के विकास के लिए सस्ती बिजली, मुफ्त सिंचाई आदि का इंतजाम करने के बारे में चौथी योजना में क्या वह कोई विचार कर रहे हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : गो मैं भी बिहार का हू लेकिन इस तरह के किसी ब्यान का मुझे पता नहीं है । मुफ्त सिंचाई, मुफ्त बिजली, मेरे ख्याल में यह एक नीति की बात है । व्यक्तिगत रूप से मैं इतना कह सकता हूं कि शायद इससे और कोई अच्छी बात नहीं हो सकती है । आप तो समाजवादी है और आप तो इस बात को जानते होंगे कि इसके लिए

एक प्राइस पालिसी होनी चाहिये । सोशलिस्ट सोसाइटी जो होती है उस में इस तरह की बात नहीं करते हैं, बढ़ावा देने की और सहायता देने की बात होती है ।

श्री यशपाल सिंह : पहले खेती के लिए हफ्ते में एक दफ़ा नहर का पानी मिलता था । अब देहातों में खेती के लिए 45 दिन में एक बार पानी मिलता है । लेकिन इस की दरें वही चली आ रही हैं । जो आबपासी टैक्स है, जो इरिगेशन टैक्स है वह ज्यों का त्यों चला आ रहा है बल्कि हाल ही में पच्चीस परसेंट बढ़ गया है यानी सौ का सवा सौ हो गया है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कैसे इन किसानों को राहत देगी । पहले हफ्ते में जहां एक बार पानी दिया जाता था वहां वही पानी अब पैंतालीस दिन में एक बार दिया जाता है और उसके सवाये चार्ज किये जाते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह से गांवों में रहने वाले किसानों को आप राहत देने का विचार रखते हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : खास जो बात आपने बताई है उसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है । राहत देने का जहां तक प्रश्न है उसके प्रयास हो रहे हैं । अधिक अन्न उपजाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है । देहाती क्षेत्रों की भलाई के और भी कई कार्य हो रहे हैं । माननीय सदस्य जो कहते हैं वह भी एक तरीका है जिससे देहाती क्षेत्रों के लोगों की भलाई हो सकती है । लेकिन जहां तक यू० पी० की बात है वहां जो कुछ परिवर्तन हुआ है, उसकी मुझे सूचना नहीं है और मैं उसको देखूंगा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : 1961 की जन गणना की रिपोर्ट के आधार पर यह हा जा सकता है कि 82 प्रतिशत भारत ां में रहता है और 18 प्रतिशत भारत हर ों में रहता है । लेकिन जितने भी जी नियरिंग कालेज हैं, मैडीकल कालेज है और दूसरे टैक्नीकल कालेज है सब के सब शहरों में केन्द्रित होते जा रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि आगे आने वाली योजनाओं में भारत सरकार क्या कुछ इस प्रकार की व्यवस्था भी कर रही है कि इस प्रकार की इंस्टीट्यूशंज देहातों की ओर भी ले जाई जायें ?

श्री ल० ना० मिश्र : इन्होंने जो आंकड़ा दिया है 82 और 18 परसेंट का यह सही है । 1951 में 83 और 17 था । 83 का 82 बन गया है और 17 का 18 हो गया है । एक परसेंट का फर्क हुआ है । किन्तु इसका कारण यह नहीं है कि लोग शहरों में अधिक हो गये हैं । लेकिन इसका कारण यह भी है कि देहात शहर बन गये हैं । लोहे के कारखानों को आप ले लीजिये । और भी कई प्राजैक्ट्स देहातों में गई हैं । उसी से उन्होंने शहरों का रूप ले लिया है । कुछ लोग देहातों से शहरों में आये होंगे । इसमें कोई शक नहीं है । लेकिन आप देखिये कि स्टील प्लाट्स, हैवी मशीन प्लाट्स देहातों में लग रहे हैं । दुर्गापुर, भिलाई वगैरह को ही देख लें । यह देखा जाना चाहिये कि देहाती इलाकों का विकास हो ताकि लोगों को वहां काम मिल सके ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा प्रश्न दूसरा था । मैंने यह कहा था कि मैडीकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज और जितनी भी टैक्नीकल इंस्टीट्यूशंज हैं वे सारी शहरों में खुल रही हैं । 82 प्रतिशत हिन्दुस्तान देहातों में रहता है । मैंने यह जानना चाहा है कि देहातों की ओर भी इन इंस्टीट्यूशंज को ले जाने की क्या कोई व्यवस्था सरकार ने की है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह आपका एक सुझाव है । इस पर भी मनन हो रहा है । दूर का मेरा खयाल है कि रूरल यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है, पालिसी है और उसको हम करना चाहते हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : सरकार ने 1954–55 में एक इनक्वायरी कराई थी कि देहाती जनता के ऊपर कितना कर्ज है। उस में यह पाया गया था कि देहाती जनता दिन-प्रति-दिन कर्जे से दबती जा रही है। वह कर्ज से मुक्त हो इसके लिए सरकार ने क्या कोई विशेष योजना बनाई है और यदि बनाई है तो वह क्या है? क्या सरकार ने हाल ही में इस बात की जांच की है कि देहाती जनता कितने कर्जे में है?

श्री ल० ना० मिश्र : इधर जांच हुई है या नहीं, मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन मुझे याद है कि एक बार रूरल क्रेडिट सर्वे हुआ था। लोग कर्ज में थे। रूरल इंडेटिडनैस था। यह बात सही है। उसके बाद कुछ चीप क्रेडिट प्रोवाइड करने की बात हुई और लैंड मार्टगेज बैंक वगैरह की योजना थी। मैं विस्तार में नहीं जा सकता हूं लेकिन इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि यह एक समस्या है जिसकी ओर सरकार का ध्यान गया है।

श्रीमती जयाबेन शाह : मारा जो आपका फोर्थ प्लान है इसको क्या आप रूरल ओरियेंटिड बनाना चाहते हैं या नहीं? क्रेडिट की बात भी की जाती है। आज तक सिर्फ तीन प्रतिशत क्रेडिट ही कोऑपरेटिव सैक्टर द्वारा दिया जाता है। मैं जानना चाहती हूं कि कौन से ऐसे मैजर्ज आप लेना चाहते हैं जिससे रूरल और अर्बन लोगों के बीच में जो इतना फासला पड़ गया है, वह कम किया जा सके? मैं कहना चाहती हूं कि स्पेसिफिक तौर पर बताया जाना चाहिये कि आप क्या करना चाहते हैं?

श्री ल० ना० मिश्र : रूरल एरियाज के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं वह मैं आपको बता चुका हूं। यह सही है कि जो फासला है लिविंग स्टैंडर्ड का, एक्सपेंडीचर का वह काफी बड़ा है। हमारी पूरी सहानुभूति देहात के लोगों के साथ है। लेकिन मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं। शहर के लोग प्रति व्यक्ति 32 रुपये और देहात के 22 रुपये खर्च करते हैं। पचास परसेंट के आस-पास का फर्क है, यह सही है। लेकिन देहात के लोगों को राहत दी जाये, इस में कोई दो रायें नहीं हैं।

श्री तन सिंह : तृतीय योजना में यह अनुमान नहीं लगाया गया है कि शहर और गांवों के क्षेत्रों में कितनी विषमता बढ़ गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि चतुर्थ योजना बनाने के अवसर पर सरकार क्या इस बात को ध्यान में रखेगी और इसका अनुमान लगायेगी और क्या भविष्य में इस विषमता को कम करने के दृष्टिकोण से योजना बनाई जा रही है?

श्री ल० ना० मिश्र : अनुपात के रूप में विषमता ज्यादा नहीं बढ़ी है। लेकिन यह बात भी सही है कि देहात के लोगों की तरक्की हो रही है और शहर लोगों की ज्यादा तरक्की हो रही है। अभी भी फर्क बहुत है। दोनों के रहन सहन में और आमदनी में भी बहुत फर्क है लेकिन यह कहा जाये कि देहात के लोगों में कोई स्टेगनेशन है और शहर के लोग ऊपर चले जा रहे हैं, यह सही नहीं है।

श्री किशन पटनायक : ग्रामीण पिछड़ेपन की एक बड़ी निशानी और वजह है प्रति व्यक्ति आय में कमी। अगर इस कमी को दूर करने के लिए मुफ्त सिंचाई और लगान मुफ्त उपाय पर आप अमल नहीं करना चाहते हैं जैसा कि अभी आपने बताया है तो किन उपायों पर आप अमल करके प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना चाहते हैं? क्या इसकी कोई योजना आपके पास है?

श्री ल० ना० मिश्र : हम चाहते हैं कि उनको साधन उपलब्ध हों सिंचाई के, बिजली के, उद्योगों के और उन से उनकी दौलत बढ़ेगी। माननीय सदस्य तो अपने आपको समाजवादी कहते हैं। वह जानते ही होंगे कि

समाजवादी समाज का विकास किस तरह से होता है . . . .

श्री किशन पटनायक : एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके लिए मुफ्त सिचाई चाहिये ।

श्री ल० ना० मिश्र : दौलत बांटने से कोई समाज अमीर नहीं होता है । साधन उपलब्ध होने चाहियें ।

श्री गणपति राम : अभी कहा गया है कि सिंचाई, बिजली और उद्योग बढ़ा कर ग्रामीण समस्याओं को हम हल करना चाहते हैं । क्या सरकार को मालूम है कि गांवों में जो शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब्स और इकोनोमिकली बैकवर्ड क्लासिस के लोग है और एग्रिकलचरल लेबर है उनके पास कोई सिंचाई और बिजली के साधन नहीं पहुंच सके हैं, इस से उनको कोई फायदा नहीं पहुंच सका है ? पिछली तीन योजनाओं में जो रुपया हाउसिंग के लिए या और चीजों के लिए रखा गया था वह भी रिटर्न हो गया । क्लासेस का रुपया भी उनके पास नहीं पहुंच सका । मैं जानना चाहता हूं कि उनके विकास के लिए सरकार क्या सोच रही है ? किस तरह से सरकार उनका आर्थिक उत्थान करना चाहती है ?

श्री ल० ना० मिश्र : खेती में जो मजदूर काम करते है सिंचाई से उनको फायदा नहीं होगा यह कहना सही नहीं है । बैकवर्ड क्लासिस के बारे में मैंने बताया है कि 188 करोड़ में से 169 करोड़ देहातों में बैकवर्ड क्लासिस के वैलफेयर के लिए हम खर्च करना चाहते हैं ।

Shri Kandappan: The statement says that in spite of the emphasis given for rural development in all the three Plans, there is marked imbalance between the development of the rural and the urban areas. Either there is no emphasis or all the three Plans have miserably failed. The statement also says: "No quantitative assessment has been made of the precise effects of the three Five Year Plans on this disparity...." May I know whether the government is in a position to give a general indication as to whether the disparity has widened or lessened after the implementation of the three plans?

Shri L. N. Mishra: I will give some figures and the hon. member can draw his own conclusion. In 1958-59 the per capita expenditure in urban areas was Rs. 28 and odd....

Shri Kandappan: I do not want any figures; I want a general indication.

Mr. Speaker: Can he say whether the disparity has widened or narrowed down?

Shri L. N. Mishra: It is a question of calculation. It was Rs. 28 as against Rs. 20. Today it is Rs. 32 as against Rs. 22.

Shri Daji: Therefore, it has widened.

Mr. Speaker: He might have it calculated and give the answer.

Shri Daji: He is the Deputy Minister of Finance and he does not know mathematics!

Mr. Speaker: He has not got it calculated.

Shri R. S. Pandey: We find there is concentration of industries in big cities. In order to improve the economic condition of the villages, may I know whether the government is thinking of decentralising industries and making them go towards the villages?

Shri L. N. Mishra: Decentralisation and dispersal of industries is one of our main policies.

Shri Ranga: Apart from the political propaganda indulged in here by this minister and other ministers also regarding this matter, does he admit or is he not aware of the fact that the disparity in facilities provided in the rural areas and in cities and also the disparity in per capita income in rural

and urban areas has increased by and large during the last 15 years? Only this morning his colleague; Dr. Rao, was saying that the rate charged for electricity for industrial use is only one-third of what is being charged for agricultural use.

Shri L. N. Mishra: I cannot say that the disparity has increased. It will be difficult for me to accept that position that the disparity has increased. I have told the House what efforts have been taken to improve the conditions of the rural population. The hon. member must realise that 82 per cent of India's population live in rural areas and only 18 per cent live in urban areas. Therefore, naturally, the people living in urban areas get better opportunities to improve their plight than the people living in rural areas. Therefore, the development in urban areas is more than in the rural areas.

Shri Daji: The exercise of the minister reminds me of the lines in Oliver Goldsmith's "Village School Master":

"Though vanquished, he could argue still!"

He says the disparity has not increased, but if we calculate from the figures he mentioned, it has definitely increased. This clearly shows that unless the whole approach gives place to a new approach of a concerted drive for rural development, more money spent on planning will only result in further growth of this disparity. Therefore, is the government going to give any thought to the reorientation of the policy so that the disparity can be narrowed consciously and in a planned manner?

Shri L. N. Mishra: It is a question of policy. The hon. member referred to political propaganda. I must enunciate and explain here what our policies are. Our policies are to develop rural areas. We stand for the rural people. It is one of the basic policies of the plan to develop rural areas. We have taken a number of measures to improve the plight of the rural people.

Creation of Asian Food Trust

+

***1489. Shri Shree Narayan Das:**
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri Subodh Hansda:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether any suggestion for the creation of the Asian Food Trust controlled by the Asian Development Bank has been made;

(b) if so, the precise nature of the suggestion and the way of its functioning;

(c) whether Government have been sounded on the point; and

(d) if so, the reaction of the Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat): (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

Shri Shree Narayan Das: May I know whether the attention of the government has been drawn to a news report in the **Hindustan Times** dated 6th January, 1966 that some such suggestion has been made to the US Government to contribute all its surplus in food for the creation of an Asian Food Trust? If so, has the government considered the implications of this, whether India would get any real advantage by the establishment of this Food Trust or whether it will be in a disadvantageous position?

Shri B. R. Bhagat: The question is whether the Asian Development Bank which is to be constituted will take up the Asian Food Trust. The Asian Development Bank has not come into being. So, the question of managing food trust or any other trust does not arise.

Shri Shree Narayan Das: The present position is that we have been importing foodgrains on a large scale from America under PL 480. Will the position improve after the creation of